an>

Title: Need to ensure participation of eligible and interested parties in coal linkage auctions of BCCL in Baghmara development block in Dhanbad, Jharkhand.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) ः कोल इण्डिया के अंतर्गत बी.सी.सी.एल. क्षेत्र के बाघमारा प्रखण्ड स्थित आठ (8) कोलियरियों मुराईडीह, शताब्दी, नदखरकी, बेनीडीह, जमुनिया, जोगीडीह, महेशपुर एवं खरखरी में लिंकेज कोयला के खरीदार नहीं के बराबर हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में कथित कोयला माफिया के एक सिंडिकेट का कब्जा है। जो भी लिंकेज होल्डर इन कोलियरियों से कोयला की खरीददारी करते हैं, उन्हें कथित रंगदारी टैक्स के रूप में प्रति टन 1150 रू. की रंगदारी बतौर लोडिंग देनी पड़ती है। इस कारण इन कोलियरियों में ऑफर के कोयला के खरीददार नहीं मिल रहे हैं और लिंकेज के कोयला को बी.सी.सी.एल. प्रबंधन को कम दामों पर बेचना पड़ रहा है। लिंकेज कोयला की खरीदारी के लिए बी.सी.सी.एल. व इ.सी.एल. के करीब 152 लिंकेज होल्डर (भद्रा मालिक) लिस्टेड हैं, लेकिन कोयला माफिया के सिंडिकेट के डर और 1150 रू. की रंगदारी नहीं देने के कारण 50 प्रतिशत लिंकेज होल्डर खरीददारी में हिस्सा तक नहीं लेते। बचे हुए 50 प्रतिशत होल्डर एफ.एस.ए. (फ्यूल सप्लाई) एग्रीमेंट से बाहर होने के डर से भाग लेते हैं, लेकिन कोयला की खरीददारी जितनी मात्रा में होनी चाहिए, उतनी खरीददारी नहीं करते हैं। ऑफर निकलने के बावजूद भी बाघमारा की कोलियरियों में कोयला की बिक्री नहीं होने से बी.सी.सी.एल. प्रबंधन को लिंकेज के कोयला को पॉवर प्लाण्टों को बेचना पड़ रहा है। लिंकेज होल्डर को ऑफर के तहत एक टन कोयला 3866 रू. में बेचा जाता है, जबकि यहीं कोयला पॉवर प्लाण्टों को सप्लाई देने पर बी.सी.सी.एल. को 2000 रू. प्रति टन ही मिलता है। ऐसे में लिंकेज के 50,000 टन कोयला पॉवर प्लाण्टों को देने से बी.सी.सी.एल. को प्रति माह 9 करोड़ 33 लाख व सालाना करीब 111 करोड़ 96 लाख का नुकसान हो रहा है। लिंकेज कोयला की बिक्री बाघमारा क्षेत्र में प्रतिमाह लगभग 50,000 टन एवं कुल मिलाकर साल का करीब 6,00,000 टन नहीं हो पा रहा है। केंद्र व राज्य सरकारों की बात करें तो लिंकेज होल्डरों द्वारा प्रति टन कोयला पर करीब 1063 रू. टैक्स दिया जाता है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकारों को प्रतिमाह 53 लाख 15 हजार रू. व सालाना करीब 63 करोड 78 लाख रू. का नुकसान हो रहा है। अगर इन क्षेत्रों में माफियाओं का दबदबा है तो इन कोलियरियों के लिए एक स्थान पर कोयला स्टॉक किया जाए एवं वहीं से उसकी बिक्री की जाए। अन्यथा इसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। कोल इण्डिया, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को हो रहे राजस्व के नुकसान से संबंधित यह एक बहुत ही गंभीर मामला है।

अतः केंद्र सरकार से मेरा आग्रह होगा कि इन कोलियरियों में लिंकेज होल्डरों को समुचित सुरक्षा प्रदान करते हुए माफियाओं पर अंकुश लगाया जाए, ताकि लिंकेज होल्डर पूरा ऑफर लगा सकें। साथ ही इस पूरे मामले की सी.बी.आई. जाँच कराई जाए, ताकि कोल इण्डिया सहित केंद्र व राज्य सरकारों को जो राजस्व का नुकसान अभी तक हुआ है, उसका पता चल सके।